



ब्रिटेन में 1976 तक जिन स्थानों पर तितलियाँ अच्छी तादाद में मिलती थीं, उनमें से आधे स्थानों से तितलियों की स्थानीय प्रजातियों का फैलाव 42 प्रतिशत तक घटा है, क्योंकि जंगल, खेतों व शहरों से तितलियाँ लुप्त हो गई हैं। जो तितलियाँ सिर्फ वेदलैंड्स और चॉक ग्रासलैंड्स जैसे विशेष हैंडिटेड में ही मिलती हैं उनकी दशा तो और भी खराब है। इनके विस्तार में 68 प्रतिशत की कमी आई है। बटर फ्लाई कंजर्वेशन, जिसने तितली के 23 मिलियन रिकॉर्ड्स के आधार पर यू.के. में तितली की स्थिति पर "बटर फ्लाई 2022" रिपोर्ट जारी की है, के वैज्ञानिकों ने कहा कि, स्थिति बहुत विनाशकारी है और इन हालात को पलटने के लिए भारी कदम उठाने होंगे। रिपोर्ट कहती है कि, कई संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षण प्रयासों से बचाया गया है और कुछ खास जगहों पर उनका सफल पुनर्वास भी किया गया है, लेकिन, ब्रिटेन के अधिकांश भागों से तितली विलुप्ति का क्रम जारी है। बटरफ्लाई कंजर्वेशन के रिचर्ड फॉक्स ने कहा, हमने तितली की सबसे ज्यादा संकटग्रस्त प्रजाति पर फोकस किया है, जिससे उनकी विलुप्ति रूक रही है। लेकिन रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि अभी कई चुनौतियाँ हैं और हमें इनसे निपटने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। वुड वाइट, ग्रेलिंग, वॉल, वाइट एडमिरल और पर्ल बोर्डर वाली फ्रिटिलरी तितलियों की आबादी में भारी गिरावट आई है। चित्र में नजर आ रही ग्रेलिंग का वितरण 92 प्रतिशत घटा है तथा 1976 से 2019 तक इनकी प्रचुरता में 72 प्रतिशत कमी आई है। जलवायु परिवर्तन और संरक्षण के प्रयास से तितली को बचाने में कुछ सफलता भी मिली है। देखा गया है कि, तापमान बढ़ने से इनका विस्तार ब्रिटेन में उत्तर की तरफ भी हुआ है। इनमें परपल एम्पर और कोमा प्रमुख हैं। लार्ज ब्लू के संरक्षण प्रयासों से फायदा हुआ है और 1979 में विलुप्ति के बाद इसकी प्रचुरता 188 प्रतिशत बढ़ गई है। हालांकि, कुछ नेचर रिजर्व में संरक्षण प्रयासों से दुर्लभ तितलियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अन्य क्षेत्रों से इनका गायब होना जारी है। नेचर रिजर्व में स्वालोटेल् की प्रचुरता 51 प्रतिशत बढ़ी है, क्योंकि इनका प्रबंधन काफी अच्छा था लेकिन अन्य क्षेत्रों में इनकी आबादी 27 प्रतिशत तक घटी है। चॉक ग्रासलैंड में मिलने वाली सिल्वर स्पॉटेड स्किपर और अडोनिसेस ब्लू तितली की प्रचुरता क्रमशः 590 प्रतिशत व 130 प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन, साथ ही इनका विस्तार क्रमशः 70 व 44 प्रतिशत घटा है।

कर्नाटक में चुनावी दबाव, कर्मचारियों के वेतन में 17 प्रतिशत की वृद्धि

राज्य सरकार ने ओल्ड पैन्शन स्कीम भी मंजूर की

—लक्ष्मण वेंकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 1 मार्च। कहा जाता है कि चुनावों से पहले कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों को नाराज करना नहीं चाहती क्योंकि चुनाव-प्रक्रिया के संपादन में उनकी अहम भूमिका हुआ करती है और कर्नाटक सरकार भी इसका अपवाद नहीं है। कर्नाटक विधानसभा के चुनावों में चन्द महीने ही शेष हैं क्योंकि मई में विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसलिये बासवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने भी हड़ताल कर रहे सरकारी कर्मचारियों के साथ ताल-मेल बिठा लिया तथा वेतन बढ़ाने की उनकी माँग के आगे समर्पण कर दिया।

बुधवार से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल के शुरू होने के कुछ घंटों के अन्दर ही, सरकारी कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि सरकार ने उनके मूल वेतन में 17 प्रतिशत की अंतरिम वृद्धि कर दी।

इस घोषणा के तुरंत बाद, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सी.एस. शंदाक्षरी ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी तथा सभी

प्रदेश की भाजपा सरकार की इस घोषणा के बाद राज्यभर में चल रही कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है।

इसी के साथ यह सवाल भी उठ रहा है कि कांग्रेस व अन्य दलों की सरकार वाले राज्यों में भाजपा की केन्द्र सरकार ओल्ड पैन्शन स्कीम का विरोध कर रही है, अब देखना यह है कि, कर्नाटक में केन्द्र सरकार का रुख क्या होगा, जहाँ भाजपा की सरकार है।

भ्रष्टाचार और 40 प्रतिशत कमीशन की सरकार का आरोप झेल रही भाजपा कर्नाटक में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए कर्मचारियों को खुश करने के लिए इतनी बड़ी घोषणा की गई है।

समर्थन ने कांग्रेस को विजयश्री दिला दी थी।

कर्नाटक में, भाजपा ने कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ा था तथा ओ.पी.एस. देने का वादा करना शुरू कर दिया था। तथा आज की घोषणा उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। सरकार ने आज घोषणा कर दी कि अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जायेगी, जो एन.पी.एस. को वापस लेने तथा ओ.पी.एस. को फिर से लाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि कमेटी से कह दिया गया है कि भारत के अन्य राज्यों में चल रही ओ.पी.एस. प्रक्रिया का अध्ययन करे। कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वेतन संशोधन/बढ़ाये जाने के लिये शुरू किया था तथा मूल वेतन में 40 प्रतिशत वृद्धि की अंतरिम राहत तथा एन.पी.एस. खत्म करने की माँग की थी। चिकित्सा एवं शिक्षा सहित विभिन्न सेवाएँ हड़ताल से प्रभावित हो गई थीं।

क्या आपको कम सुनाई देता है!
कान की मशीनें
स्पीच थेरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaidhali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingolutions.com

बी.बी.सी. पर रेड का मुद्दा उठाया
ब्रिटिश विदेश मंत्री ने
—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 1 मार्च। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवर्ली ने बुधवार को कहा कि गत माह भारत में बीबीसी कार्यालयों की जाँच पड़ताल के मुद्दे को भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर के साथ

■ ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली जी-20 की बैठक में हिस्सा लेने भारत आए हैं, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बी.बी.सी. पर रेड का मुद्दा उठाया।

हुई द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान उठाया गया था।
क्लेवर्ली इस समय जी 20 विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने के लिये भारत आये हुये हैं। उन्होंने जयशंकर के साथ हुई मीटिंग में दिल्ली तथा मुम्बई में बीबीसी की टैक्स तलाशी के मुद्दे को उठाया। अनाम सूत्रों के अनुसार "उनसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सख्त मल (कब्ज) व पेट की परेशानियों का आयुर्वेदिक उपचार
जगृवी
www.jagraviherbal.com

इन्टरनेट पर राहुल गांधी के नए "लुक" ने हंगामा मचाया

—डॉ सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 1 मार्च। राहुल गांधी के नए लुक "लम्बे बाल बिखरी सी दाढ़ी" ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है लेकिन भाजपा टोल्स जहाँ इस पर हमला कर रहे हैं वहीं अन्य राहुल की तारीफ के कसौदे लिख रहे हैं।

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जो एक माह पहले खत्म हुई है, के दौरान राहुल ने बाल व दाढ़ी बढ़ा ली थी। इस यात्रा में उन्होंने 150 दिनों में 2 राज्यों दो केन्द्र शासित प्रदेशों में यात्रा की थी। राहुल इस समय लंदन में हैं, जहाँ उन्हें कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी में लैक्चर देना है। राजस्थान युवक कांग्रेस ने राहुल के नए लुक की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और लिखा कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में नए लुक के साथ।

एक अन्य ने राहुल की और तस्वीरें शेयर की और लिखा "कैम्ब्रिज लैक्चर से पहले राहुल का नया लुक एक अन्य ने लिखा" मार्क्स स्टालीन की दाढ़ी इतिहास है" राहुल गांधी के लम्बे बाल और दाढ़ी यात्रा के दौरान चर्चा का विषय रही। इटली के एक दैनिक को दिए एक इंटरव्यू में गांधी ने अपनी दाढ़ी पर पूछे गए एक सवाल पर कहा कि "मैंने तय किया है कि" मैं मार्च तक इसे नहीं काटूंगा। अब मुझे देखना है कि मैं इस रखू या नहीं। एक ट्विटर यूजर अरुण यादव, जो राहुल विरोधी तथा कांग्रेस विरोधी ट्वीट्स के लिये जाने जाते हैं, ने लिखा "पप्पू ने कटवा ली" तथा इसके साथ राहुल का एक ताजा फोटोग्राफ लगा दिया।

इससे पूर्व 8 फरवरी को गृह राज्यमंत्री हर्ष साँघवी ने राहुल पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुये ट्वीट किया था "अब एक चीज की तो पुष्टि हो गई है, तो उससे केवल दाढ़ी बढ़ती है, अकल नहीं।"

इस ट्वीट पर गुजरात के कांग्रेसी नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएँ आईं तथा गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं बड़गाँव विधायक जिग्नेस मेवाने ने जवाब दिया, "अब एक और बात की पुष्टि हो गई। भले ही आप केवल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

74 दवाओं का मूल्य नियंत्रित

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 1 मार्च। नेशनल मैडिसिन प्राइस फिक्सेशन अथॉरिटी के द्वारा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एवं 72 अन्य दवाओं को मूल्य नियंत्रण (प्राइस कंट्रोल) के दायरे में लाया गया है। अथॉरिटी ने एक नया ड्रग्स प्राइस कंट्रोल आदेश जारी किया है, जिसके

■ नेशनल मैडिसिन प्राइस फिक्सेशन अथॉरिटी ने डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की दवा व 72 अन्य दवाओं का मूल्य निर्धारित कर दिया है।

तहत डायबिटीज की दवा मैटफॉर्मिन (500 एम.जी.) का मूल्य 27.75 ₹. प्रति टैबलेट निर्धारित किया है। हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं के संदर्भ में, टैलमिसार्टन एवं बाइसोप्रोलॉल टैबलेट का मूल्य 10.32 ₹. प्रति टैबलेट होगा, जबकि सोडियम वॉलप्रेट (200 एम.जी.) का अधिकतम मूल्य 3.20 ₹. प्रति टैबलेट होगा।

मेघालय में सरकार बनाने के लिए उठा पटक शुरू

27 फरवरी को हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आज घोषित होंगे

—अंजय राय—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 1 मार्च। मेघालय तथा अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों, जहाँ 27 फरवरी को चुनाव हुये थे, में सरकारें बनाने के लिये राजनैतिक उठापटक शुरू हो गई है तथा संबंधित राजनेता साँस रोक कर सरकार बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

चुनाव-परिणाम गुरुवार, 2 मार्च को घोषित होने हैं। प्रथम दृष्टया, मेघालय में, भाजपा-एन.पी.पी. सरकार बनने की संभावना दिखाई दे रही है तथा अधिकार पर्यवेक्षकों का मानना है कि त्रिपुरा तथा नागालैण्ड में व्यवस्था/सरकारें अपरिवर्तित रहेगी।

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरॉड संगमा पिछली रात असम के मुख्यमंत्री के साथ आधी रात के समय चर्चा की। नोर्टिंस की त्वरित अदला-बदली के बाद, कोनरॉड संगमा आज सुबह अपने घर लौटे।

यह मीटिंग दो पुराने मित्रों के बीच हुई मीटिंग बताई गई, जबकि राजनैतिक हलकों में इसे मेघालय में सरकार बनाने के लिये शुरुआती विचार-विमर्श के रूप में लिया जा रहा है।

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरॉड संगमा पिछली रात असम के मुख्यमंत्री के साथ आधी रात के समय चर्चा की। नोर्टिंस की त्वरित अदला-बदली के बाद, कोनरॉड संगमा आज सुबह अपने घर लौटे।

यह मीटिंग दो पुराने मित्रों के बीच हुई मीटिंग बताई गई, जबकि राजनैतिक हलकों में इसे मेघालय में सरकार बनाने के लिये शुरुआती विचार-विमर्श के रूप में लिया जा रहा है।

■ मेघालय के मुख्यमंत्री कौनराड संगमा की असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिस्वा सरमा से मुलाकात ने राज्य में भाजपा-एन.पी.पी. सरकार बनने की संभावना को मजबूत किया है।

■ इस बार खंडित जनादेश मिलने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए विभिन्न गठबंधन बनने की चर्चा चल रही है।

कांग्रेस, जिसने मेघालय में पहले सरकार बनाई थी, को गच्च देकर, कोनरॉड के नेतृत्व में एन.पी.पी. तथा भाजपा सत्ता में आ गई थी। दरअसल, हुआ यह था कि एक अन्य संगमा, मुकुल संगमा के नेतृत्व में करीब आधे कांग्रेसी विधायक कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गये थे तथा तत्कालीन कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी।

इस उठापटक का नतीजा यह हुआ था कि कांग्रेस सरकार गिर गई तथा कोनरॉड संगमा, राज्य भाजपा के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री बन गये थे।

चूँकि इस बार के चुनावों में बिखरा हुआ जनादेश मिलने की संभावना है

तथा किसी भी अकेले प्रमुख दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, इसलिये गठबंधन की चर्चाएँ ज़ोरों पर हैं। तथा सर्वाधिक संभव एवं आसान गठबंधन भाजपा और एन.पी.पी. का पुराना गठबंधन ही हो सकता है।

वस्तुतः अगर चुनाव परिणामों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है तो पूर्वोत्तर में कांग्रेस के लिये बहुत ज्यादा घातक धक्का माना जायेगा। अब तक, मेघालय की राजनीति में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है तथा पूर्वोत्तर के एक घोर और पुराने कांग्रेस परिवार के एक सदस्य के नेतृत्व के कारण, सत्ता से बेदखल होने तक, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूरी तरह कंगाल हो चुके पाकिस्तान के "डिफॉल्टर" होने की संभावना अति प्रबल हुई

दूसरी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने भी पाकिस्तान की रेटिंग बहुत गिराई

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 1 मार्च। पाकिस्तानी की तकलीफें लगातार बढ़ रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी फिच के बाद मूडी ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग सी.ए.ए. वन से घटा कर सी.ए.ए. थ्री कर दी है। सी.ए.ए. 3 रेटिंग पाकिस्तान की लगातार बढ़ती जा रही वित्तीय जरूरतें, अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार तक पहुंच का अभाव, ऋण की निम्न वहन-क्षमता तथा मध्यम अवधि के विश्ववसनीय राजस्व एवं वित्तीय ढांचे की कमी को दर्शा रही है। यह पाकिस्तान की क्रेडिट क्षमता का मापन करता रहेगा।

मूडी'ज इन्वेस्टर सर्विस ने घोषित कर दिया है कि "बढ़ते जा रहे नकदी संकट तथा विदेशों में इसकी स्थिति के फलस्वरूप पाकिस्तान के "डिफॉल्ट रिस्क" (कर्ज नहीं चुका पाने के खतर) सामने आ रहे हैं। लेकिन इस रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के बारे में राय व अपना नजरिया नकारात्मक/ऋणात्मक से बदलकर स्थिर कर दिया है।

मूडी'ज ने कहा था कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत अधिक नीचे गिर चुका है। यह भंडार उस निम्न सीमा से भी कम हो गया है जो आयात की जरूरतों का पूरा करने तथा तुरंत अदा करने वाले तथा मध्यम अवधि के विदेशी कर्ज के भार के लिहाज से अत्यावश्यक होती है।

■ एजेंसी ने देश की "डेट रेटिंग" सी.ए.ए.1 से घटाकर सी.ए.ए.3 कर दी है।

■ इससे पहले एक अन्य इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फिच भी पाकिस्तान की रेटिंग में भारी कटौती कर चुकी है।

■ पाकिस्तान की सारी उम्मीदें आई.एम.एफ. के कर्ज पर हैं, पर उसमें भारी मुश्किलें हैं, चुनावी वर्ष में आई.एम.एफ. की शर्तों को मानना आसान नहीं है।

■ हालांकि पाकिस्तान ने आई.एम.एफ. की शर्तें मानने का प्रयास शुरू कर दिया है, इसके तहत सभी प्रकार के बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है, जिसमें वेतन बिल भी शामिल हैं। इससे पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है।

रेटिंग एजेंसी का कहना है कि सरकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आई.एम.एफ.) के प्रोग्राम और आर्थिक अनुदान दिए जाने की शर्तों के अनुरूप को कुछ कर सुधार लागू कर रही है ताकि देश की फौरी राहत मिल सके।

इसने कहा कि, कमजोर सरकार और बढ़ते सामाजिक खतरों ने भुगतान के संतुलन से लेकर तमाम वित्तीय खतरों से निपटने की पाकिस्तान की क्षमता को प्रभावित किया है।

मूडी ने कहा कि उसने पाकिस्तान को जो "इटेबल आउट लुक" स्तर दिया है उसका अर्थ है कि पाकिस्तान सी.ए.ए. रेटिंग लेवल के खतरों का सामना लगातार कर रहा है।

नकदी संकट से त्रस्त पाकिस्तान सरकार ने एकाउन्टेंट जनरल को सभी बिलों को मंजूरी देने से रोक दिया, जिसमें वेतन भी शामिल है। वर्तमान आर्थिक संकट की वजह से यह कदम उठाया गया है।

वित्त और राजस्व मंत्रालय ने पाकिस्तान रैवेन्यू एकाउन्टेंट जनरल को केन्द्रीय मंत्रालयों और संबंधित विभागों के बिल अगली सूचना तक स्वीकृत करने पर रोक लगा दी है। यह जानकारी न्यूज इंटरनेशनल के सूत्रों ने दी है।

न्यूज इंटरनेशनल ने बताया कि ऑपरेशनल कॉस्ट रिलेटेड रिलीज़ में भी मुश्किलें आ रही हैं। पाकिस्तान का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में नैटबंदी के खिलाफ याचिका स्वीकार की

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 1 मार्च। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने, प्रतियोगी परीक्षा में नकल को रोकने के लिए राजस्थान में

■ सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में सरकार द्वारा की गई तीन दिन की नैटबंदी के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और इस पर होली अवकाश के बाद सुनवाई होगी।

की गई तीन दिन की नैटबंदी के बारे में सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी। यह सुनवाई होली ब्रेक के बाद होगी। कोर्ट में अगले पूरे सप्ताह, 6 से 10 मार्च तक अवकाश रहेगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)